

## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजीविका और NGO प्रदान (PRADAN) की 'सांझी पहल'
2.	'एडवांस 28-ft हेवी ड्रॉप सिस्टम - 20T (टाइप V)' का सफल परीक्षण
3.	पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का राजस्थान पर प्रभाव
4.	84th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ऑपथोलॉजिकल सोसाइटी
5.	नदी प्रदूषण पर गठित 'हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी' की रिपोर्ट
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. आयुर्वेद आधारित पॉडकास्ट स्टूडियो 2. राजस्थान सोलर एसोसिएशन का 'खेजड़ी से कल' अभियान 3. पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान 4. आर्यन यादव 5. पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार
7.	निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) फ्रेमवर्क
8.	राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड
9.	किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
10.	NHRC लघु फिल्म पुरस्कार
11.	संसदीय प्रश्न : न्यायपालिका सशक्तीकरण
12.	शैडो फ्लीट (Shadow Fleet)
13.	खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
14.	तेहरान में ब्लैक रेन
15.	स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)
16.	मैग्नेटिक सेमीकंडक्टरों में हीट ट्रांसपोर्ट
17.	सी-डॉट और "फ्रॉडप्रो"
18.	CE-20 क्रायोजेनिक इंजन



## राजस्थान परिदृश्य



### राजीविका और NGO प्रदान (PRADAN) की 'सांझी पहल'



#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) और NGO प्रदान (PRADAN) की सांझी पहल के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।



#### मुख्य बिन्दु:

- कार्यशाला का उद्घाटन :** ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह तथा राजीविका की राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरि द्वारा।
- इस पहल के तहत 'राजीविका' और 'प्रदान' के सहयोग से राज्य में कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) परिवारों की आय में वृद्धि के लिए तकनीकी सहयोग, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पहल के तहत चयनित जिलों में समुदाय आधारित संगठनों को सशक्त करने, आजीविका गतिविधियों की गुणवत्ता सुधारने और लखपति दीदी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 'सांझी पहल' को प्रारंभिक चरण में प्रदेश के आठ जिलों के चयनित ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जाएगा।
- चयनित ब्लॉक :** राजगढ़ (अलवर), जोथरी व सीमलवाड़ा (डूंगरपुर), बाली (पाली), सुहागपुरा (प्रतापगढ़), झालरा, लसाड़िया, सलूंबर व जयसमंद (सलूंबर), आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर व शिवगंज (सिरोही), खमनोर (राजसमंद) तथा गोगुन्दा, सायरा, भिंडर व कुराबड़ (उदयपुर)।

## फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

### राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) या राजीविका

- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) या राजीविका की स्थापना वर्ष 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।
- यह राजस्थान सोसायटी अधिनियम - 1958 के तहत पंजीकृत सोसायटी है।
- **अध्यक्ष** : मुख्यमंत्री।

### उद्देश्य:

- ग्रामीण विकास के लिए की जा रही सरकारी और गैर-सरकारी पहलों के बीच प्रभावी अभिसरण लाना।
- स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संगठनों, सामुदायिक विकास संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के गठन और सुदृढीकरण में सहायता करना।
- गरीबों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना।

## 'एडवांस 28-ft हेवी ड्रॉप सिस्टम - 20T (टाइप V)' का सफल परीक्षण

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय सेना द्वारा पूर्ण रूप से स्वदेश में विकसित 'एडवांस 28-ft हेवी ड्रॉप सिस्टम - 20T (टाइप V)' का सफल परीक्षण किया गया।



### मुख्य बिन्दु:

- परीक्षण स्थल : महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर।
- डिजाइन और विकास : JCBL ग्रुप की कंपनी 'एयरबोनिक्स डिफेंस एंड स्पेस' द्वारा विकसित इस सिस्टम को DRDO के 'एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट' के साथ साझेदारी में बनाया गया है।

--:4:--

# Daily Current Affairs

Date : 13 March, 2026



- **उद्देश्य :** यह हेवी ड्रॉप सिस्टम दूरदराज के इलाकों में भारी सैन्य वाहनों और उपकरणों को हवाई मार्ग से गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **कार्यप्रणाली :** यह हेवी ड्रॉप सिस्टम परिवहन विमानों से बड़े कार्गो और मशीनीकृत सैन्य प्लेटफॉर्म को तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 20 टन तक के पेलोड को संभालने में सक्षम है और लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस तथा बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर जैसे विमानों के लिए अनुकूल है।
- इस सिस्टम में एक नया विकसित 28 फीट का प्लेटफॉर्म और पैराशूट सेटअप शामिल है। इस व्यवस्था में दो 28-फीट के एक्सट्रैक्टर पैराशूट के एक सेट का उपयोग किया जाता है, जिसके साथ चार-पॉइंट लिंक सिस्टम भी जुड़ा होता है।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

--5--

## पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का राजस्थान पर प्रभाव

### चर्चा में क्यों?

- पश्चिमी एशिया में जारी ईरान और इज़राइल, अमेरिका के बीच संघर्ष का राजस्थान पर सीधा और गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। मार्च, 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था के पर्यटन और निर्यात क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है।



### मुख्य बिन्दु:

#### पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग पर प्रभाव:

- युद्ध के डर और हवाई मार्ग के बाधित होने के कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों ने राजस्थान की अपनी यात्राएँ बड़े पैमाने पर रद्द कर दी हैं। जैसलमेर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में विदेशी पर्यटकों की बुकिंग में भारी गिरावट देखी गई है।

# Daily Current Affairs

Date : 13 March, 2026



- राजस्थान विश्वभर में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाना जाता है। संघर्ष के परिणामस्वरूप डेस्टिनेशन वेडिंग में भी गिरावट आई है।
- होली के त्योहार से पहले खाड़ी संकट से पर्यटन क्षेत्र पर भी गंभीर प्रभाव दृश्य है, जहाँ कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द होने के कारण पर्यटन सीजन में भी पर्यटकों की कमी है।

## ऊर्जा संकट और महंगाई:

- राजस्थान में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की भारी किल्लत हो गई है क्योंकि तेल कंपनियाँ घरेलू खपत को प्राथमिकता दे रही हैं।
- औद्योगिक क्षेत्रों में गैस आपूर्ति न होने के कारण क्रॉकरी और अन्य मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो सकती है, जिससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ सकता है।
- वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें \$110 प्रति बैरल तक पहुँचने से आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की संभावना है।

## व्यापार और निर्यात में गिरावट

- राजस्थान का प्रमुख टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित है। खाड़ी देशों और यूरोप को होने वाले लगभग ₹800 से ₹1000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट के कारण जयपुर का रत्न और आभूषण व्यवसाय भी मंदी की चपेट में है।

--7--

## 84th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ऑपथल्मोलॉजिकल सोसाइटी

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जयपुर में 84th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ऑपथल्मोलॉजिकल सोसाइटी का आयोजन किया गया।



### मुख्य बिन्दु:

- आयोजन अवधि : 12 से 15 मार्च, 2026
- आयोजन स्थल : जयपुर एग्जीबिशन & कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा, जयपुर।
- आयोजक : राजस्थान ऑपथल्मोलॉजिकल सोसाइटी।
- थीम : 'हेल्थी आईज-हैप्पी लाईव्स'।
- इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 8 हजार से अधिक वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं शोधकर्ताओं ने भाग लिया।
- इस कॉन्फ्रेंस में साइंटिफिक सेशन, लाइव सर्जरी ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया।
- पुरस्कार : मुख्यमंत्री ने डॉ. तारा प्रसाद दास एवं डॉ. एस नटराजन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया।

## नदी प्रदूषण पर गठित 'हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी' की रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पश्चिम राजस्थान की प्रमुख नदियों; जोजड़ी, बांडी और लूनी के प्रदूषण की स्थिति पर गठित 'हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी' ने 202 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी।

### मुख्य बिन्दु:

- ज्ञातव्य है कि जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में जोजड़ी नदी के प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की गई थी।
- इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट की ओर से 21 नवंबर, 2025 को हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य इन नदियों के प्रदूषण के कारणों की जांच करना और उनके पुनरुद्धार के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करना था।

### हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी (HLEOC)

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति की निगरानी और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी (HLEOC) का गठन किया है।
- **अध्यक्ष :** जस्टिस (रिटायर्ड) संगीत लोढ़ा।
- **प्रमुख सदस्य :** अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण विभाग), सदस्य सचिव (CPCB और RSPCB), मैनेजिंग डायरेक्टर (RIICO) और जोधपुर, पाली, बालोतरा के जिला कलेक्टर।

### फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

### जोजड़ी नदी:

- **उद्गम :** नागौर जिले के पुंडलू गाँव की पहाड़ियों से।
- **कुल लंबाई :** 150 किमी.। यह लूनी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है।
- जोजड़ी नदी जोधपुर से होकर बहती है और दक्षिण-पश्चिम में बालोतरा में प्रवेश करती है और सिवाना के पास लूनी नदी में मिल जाती है।
- यह लूनी की एकमात्र दाईं ओर की सहायक नदी है।
- **लूनी की अन्य सहायक नदियाँ :** जवाई, सुकड़ी, गुहिया, बांडी, जोजड़ी, मीठड़ी और खारी नदी।

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>आयुर्वेद आधारित पॉडकास्ट स्टूडियो</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA), जयपुर में आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शन में देश का पहला आयुर्वेद आधारित पॉडकास्ट स्टूडियो स्थापित किया गया।</li><li>यहाँ विशेषज्ञ रोगों और उनके आयुर्वेदिक उपचार पर प्रामाणिक जानकारी साझा करते हैं। इसके एपिसोड संस्थान के सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध होते हैं।</li><li><b>उद्घाटन :</b> संस्थान के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताप राव जाधव द्वारा। पॉडकास्ट का शुरुआती एपिसोड केंद्रीय मंत्री ने रिकॉर्ड किया। इसका उद्देश्य डिजिटल पहुंच, शैक्षणिक संचार और जन सहभागिता को मजबूत करना था।</li></ul>
2.	<p><b>राजस्थान सोलर एसोसिएशन का 'खेजड़ी से कल' अभियान</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, राजस्थान सोलर एसोसिएशन (RSA) और नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) द्वारा संयुक्त रूप से 'खेजड़ी से कल' अभियान की शुरुआत गई।</li><li>इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के राज्य वृक्ष 'खेजड़ी' का संरक्षण करना और इसे अक्षय ऊर्जा (सौर ऊर्जा) के साथ जोड़कर एक टिकाऊ भविष्य बनाना है।</li><li>अभियान के तहत राजस्थान सोलर एसोसिएशन प्रदेश में 10 लाख खेजड़ी के पेड़ लगाएगा।</li></ul>

3.	<p style="text-align: center;"><b>पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में महिला सशक्तीकरण और उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए 'पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान' प्रदान किया गया।</li><li>■ <b>रेणु चौधरी</b> : सरदारशहर (चूरू) की प्राचार्य, जिन्हें समाज सेवा, चिकित्सा सहायता और महिला उत्थान के क्षेत्र में।</li><li>■ <b>राहड़ा फाउंडेशन</b> : उदयपुर जिला स्तर पर उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण (गो काष्ठ अभियान) के लिए।</li><li>■ <b>अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चेतना भाटी</b> : जयपुर में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के क्षेत्र में योगदान के लिए।</li><li>■ <b>डॉ. सविता राठौड़</b> : बूंदी में महिला सशक्तीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों के लिए।</li></ul>
4.	<p style="text-align: center;"><b>आर्यन यादव</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ हाल ही में, जयपुर के बॉक्सर आर्यन यादव ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स - 2026 में 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।</li><li>■ यह चैंपियनशिप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1 से 8 मार्च, 2026 तक आयोजित की गई थी।</li></ul>
5.	<p style="text-align: center;"><b>पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ हाल ही में, मुक्ति संस्था, बीकानेर के तत्वावधान में पाँचवें पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई।</li><li>■ <b>संतोष चौधरी (जोधपुर)</b> : राजस्थानी कहानी संग्रह "काया री कळझळ" के लिए 'राजस्थानी महिला लेखन का पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार'।</li><li>■ <b>भंवरलाल भ्रमर (बीकानेर)</b> : कहानी संग्रह "ऊपरलो पासो" के लिए राजस्थानी कथा पुरस्कार।</li></ul>



### निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) फ्रेमवर्क



#### चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) फ्रेमवर्क लागू किया।



#### मुख्य बिन्दु:

- उच्चतम न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ वाद में अपने निर्णय में, 12 वर्षों से अधिक समय से वेजिटेटिव स्टेट (चेतनाहीन अवस्था) में पड़े एक व्यक्ति की कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी है। यह निर्णय 'मरीज के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत' के आधार पर लिया गया है।
- न्यायालय ने सामान्य 30 दिनों की विचार अवधि की शर्त को हटा दिया, क्योंकि मरीज के माता-पिता और मेडिकल बोर्ड्स ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की थी कि मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है।
- **इच्छामृत्यु (Euthanasia):** यह रोगी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने की एक पद्धति है। इच्छामृत्यु के दो प्रकार हैं- सक्रिय इच्छामृत्यु और निष्क्रिय इच्छामृत्यु। इसे केवल एक चिकित्सक द्वारा प्रशासित किया जा सकता है।

#### सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia):

- इसमें चिकित्सक द्वारा जानबूझकर, आमतौर पर प्राणघातक दवाओं के माध्यम से, लाइलाज या गंभीर रूप से बीमार रोगी के जीवन को समाप्त करना शामिल है।
- **भारत में स्थिति:** सक्रिय इच्छामृत्यु भारत में अवैध है।
- नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में यह कानूनी है।

--:12:--

## निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)

- इसके तहत, जीवन को बनाए रखने वाले चिकित्सा उपचार को रोककर या वापस लेकर रोगी की प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने दी जाती है।

## कानूनी स्थिति

- **अरुणा रामचंद्र शानबाग मामला (2011):** उच्चतम न्यायालय ने इच्छामृत्यु की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन टर्मिनली इल और अपरिवर्तनीय रोगियों के लिए सख्त शर्तों के तहत 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' की अनुमति दी थी।
- **कॉमन कॉज़ निर्णय (2018):** उच्चतम न्यायालय ने इसे मान्यता दी और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने का अधिकार एक मूल अधिकार है।
- इस मामले में दिशा-निर्देश तय किए गए और लिविंग विल की अवधारणा को मान्यता दी गई।
- न्यायालय ने कहा कि 'एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स' का उपयोग करके निष्क्रिय इच्छामृत्यु दी जा सकती है।
- **2023 में जारी संशोधित दिशा-निर्देश:** वेजिटेटिव स्टेट में मरीज की जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने पर विशेषज्ञों की राय के लिए एक प्राथमिक और एक माध्यमिक मेडिकल बोर्ड का गठन करना अनिवार्य होगा।

## निर्णय के अन्य मुख्य अंश

- **व्यापक कानून बनाना:** न्यायालय ने संसद से जीवन का अंत संबंधी देखभाल और निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित एक व्यापक व सुसंगत वैधानिक ढांचा बनाने का आग्रह किया।
- **प्रशासनिक निर्देश:** भविष्य के मामलों की प्रक्रिया में सुधार के लिए, न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी मेडिकल बोर्ड जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने का निर्णय लें, तो अस्पतालों द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सूचित किया जाए।

## राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड

### चर्चा में क्यों?

- सरकार ने वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के बीच भारत के जहाजरानी क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की।

### मुख्य बिन्दु:

#### राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड (NSB)

- यह भारत का जहाजरानी और समुद्री मामलों पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है, जिसका गठन व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 की धारा 23 के तहत किया गया है।
- यह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- इसका प्राथमिक कार्य जहाजरानी नीतियों और समुद्री विकास पर केंद्र सरकार को सलाह देना है।
- इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

## आर्थिक घटनाक्रम

### किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

#### चर्चा में क्यों?

- सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की पहुँच, कवरेज और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं।

#### मुख्य बिन्दु:

- किसान क्रेडिट कार्ड छोटे, सीमांत, काशतकार किसानों और स्वयं सहायता समूहों सहित किसानों को समय पर, किफायती और बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करता है।

#### किसान क्रेडिट कार्ड

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 1998 में शुरू किया गया था।
- उद्देश्य:** फसल उत्पादन के लिए अल्पकालिक संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुँच को सरल और त्वरित बनाना।
- यह संबद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण प्रदान करता है और फसल कटाई के बाद और विपणन खर्चों को कवर करता है, जिससे कृषि आय बढ़ाने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत, ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, और बिना गारंटी के ऋण की सीमा प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है।



## Features of the KISAN CREDIT CARD SCHEME

RuPay-enabled KCC Card providing ATM-based withdrawals, digital payments and any number of withdrawals within the sanctioned credit limit

One-time documentation with provision for built-in cost escalation in credit limits over the operating cycle

Coverage of post-harvest expenses, produce marketing loans, household consumption needs, working capital for maintenance of farm assets, and activities allied to agriculture

Extension of the scheme since 2004 to meet investment credit requirements for allied and non-farm activities

Implementation across Commercial Banks, Regional Rural Banks (RRBs), Small Finance Banks and Cooperative Banks, ensuring wide institutional outreach.



Source: Department of Agriculture and Farmers Welfare

### केसीसी के पात्र लाभार्थी:

- व्यक्तिगत किसान और संयुक्त ऋणकर्ता जो स्वामी-कृषक हैं,
- किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार।
- इस योजना में स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह भी शामिल हैं, जिनमें किरायेदार किसानों और बटाईदारों द्वारा गठित समूह भी शामिल हैं।

# Daily Current Affairs

Date : 13 March, 2026



**CIVIL SERVICES**



## Progress of Kisan Credit Card (As of March 2026)

Total number of banks onboarded



**37**  
COMMERCIAL  
BANK



**46**  
RURAL  
BANK



**374**  
COOPERATIVE  
BANK

Total number of KCC/ISS applications (in Lakhs)



**631.5**  
COMMERCIAL  
BANK



**337.2**  
RURAL  
BANK



**1030**  
COOPERATIVE  
BANK

Source : Department on Agriculture and Farmers Welfare

UTKARSH

CIVIL SERVICES

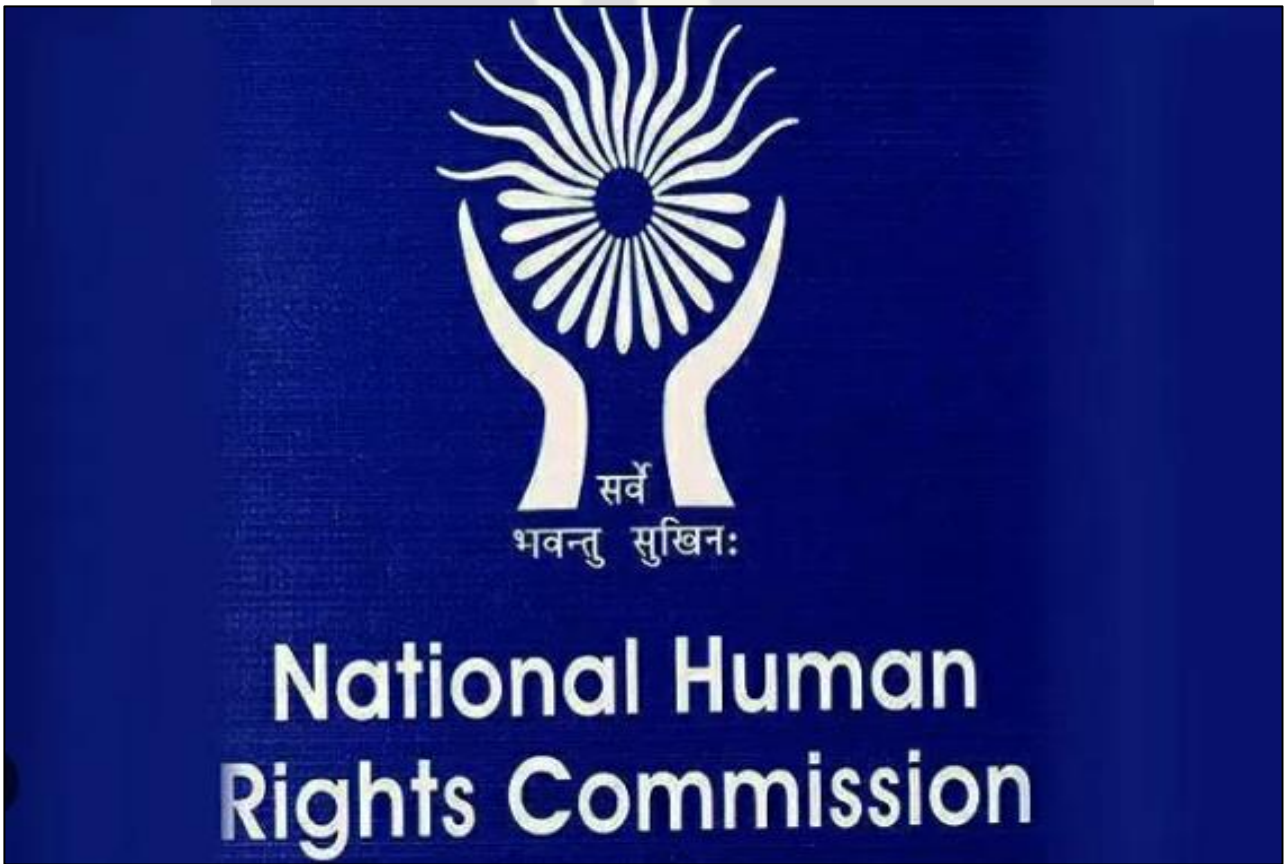
-:17:-

## भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

### NHRC लघु फिल्म पुरस्कार

#### चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने वर्ष 2025 के लिए मानवाधिकारों पर लघु फिल्मों की 11वीं वार्षिक प्रतियोगिता के 7 विजेताओं की घोषणा की।



#### मुख्य बिन्दु:

- चयन; निर्णायक मण्डल (जुरी) की अध्यक्षता : NHRC सदस्य विजया भारती सयानी
- पुरस्कार की स्थापना: वर्ष 2015
- उद्देश्य : नागरिकों को मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मुद्दों को उठाना, जागरूकता फैलाना और रचनात्मक योगदान को प्रोत्साहित करना।

# Daily Current Affairs

Date : 13 March, 2026



## ■ विजेता लघु फिल्में:

पुरस्कार	फिल्म	भाषा	निर्माण/ निर्देशक	राशि	विवरण/ विषय-वस्तु
प्रथम पुरस्कार	"रानी" (उत्तरप्रदेश)	हिंदी	सारिका जैन	₹ 2 लाख	रूढ़िवादी धारणाएँ वर्ग विभाजन और असमानता को बढ़ावा देती है।
द्वितीय पुरस्कार	"मीनव्हाइलशी" (केरल)	मलयालम	अमल एस	₹ 1.5 लाख	लैंगिक रूढ़िवादीता और घरेलु हिंसा की चुनौतियों के बीच कामकाजी महिलाओं पर असमान बोझ को उठाती है।
तृतीय पुरस्कार	"दी डिलीवरी" (तमिलनाडु)	तमिल	साई शशांक ताती	₹ 1 लाख	गिग वर्कर्स के संघर्षों को दिखाती है।

## ■ 4 लघु फिल्मों को "विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र" व 50 हजार रुपये की नकद राशि:

फिल्म	निर्माण/निर्देशक	भाषा	विषय वस्तु
'मालती'(पश्चिम बंगाल)	फाल्गुनी भक्त	बंगाली	एक आदिवासी महिला द्वारा अपने समुदाय में शिक्षा के प्रयास।
'सेकंड चांस' (उत्तरप्रदेश)	रवि कर्णवाल	हिंदी	उत्तराखंड जेल पर आधारित है।
'डस्क ऑफ लाइफ' (महाराष्ट्र)	दामोदर डी. पंवार	मराठी	निसंतान वृद्ध आदिवासी दंपति के संघर्षों और आजीविका व जीवन के अधिकार को दर्शाती है।
'भाग्यश्री' (महाराष्ट्र)	मनोज जानवेकर	मराठी	ग्रामीण परिवारों में युवा विधवाओं के संघर्षों और गरिमामय जीवन के अधिकार पर प्रकाश डालती है।

--:19:--

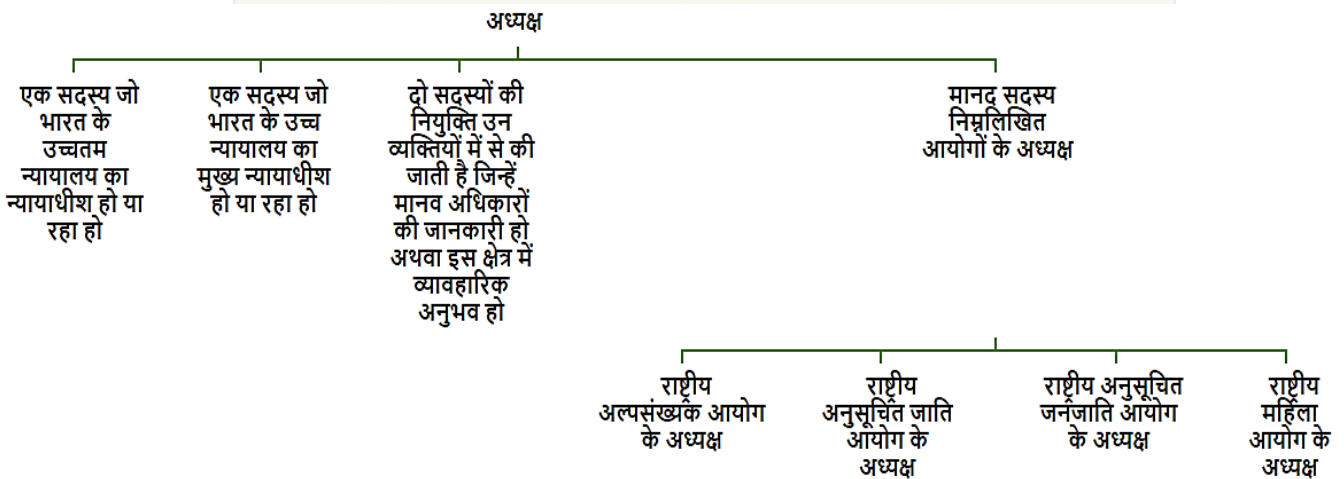
## अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

### राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग:

- **स्थापना:** 12 अक्टूबर, 1993 (मानवाधिकार दिवस : 10 दिसंबर)।
- **वैधानिक :** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (संशोधन : वर्ष 2006) ।

### संरचना :

- **अध्यक्ष :** भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश (वर्ष 2019 में संशोधन के बाद)
- **सदस्य :** 5 पूर्णकालिक सदस्य + 7 मानद सदस्य (महिला, SC, ST, उपसमूह, अल्पसंख्यक, बाल अधिकार, दिव्यांग आयोगों के अध्यक्ष)



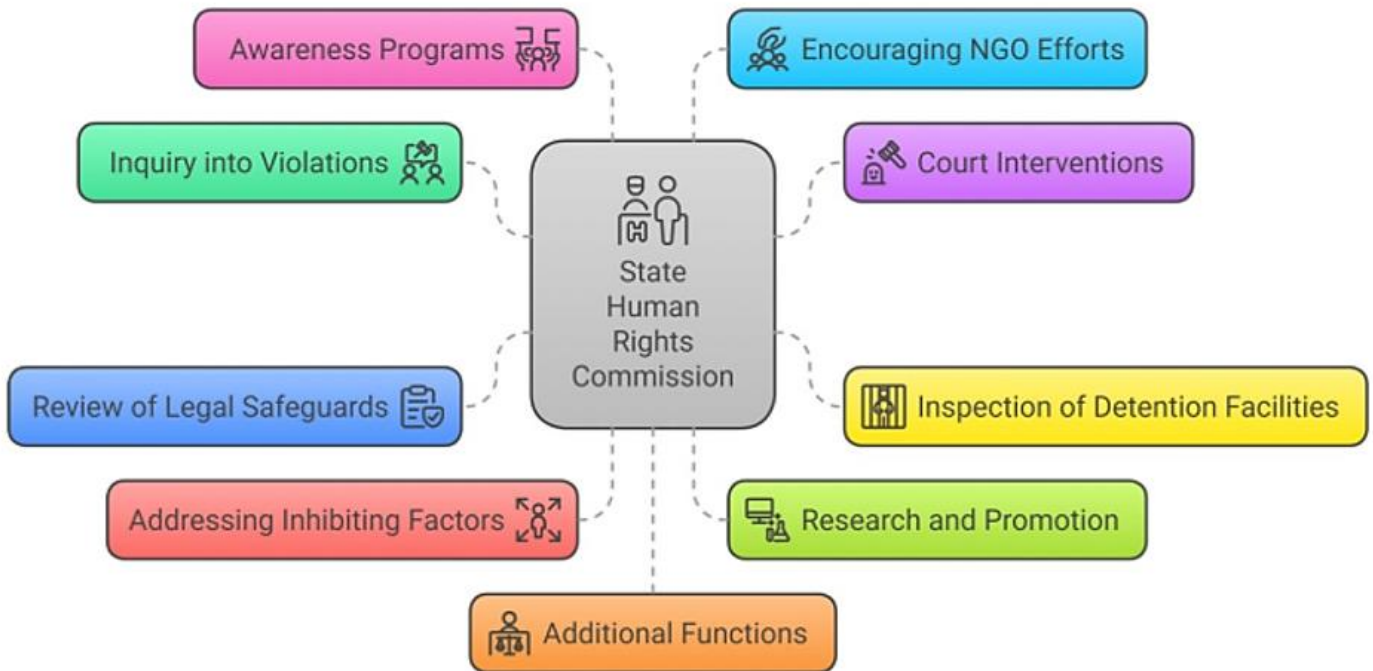
- **नियुक्ति :** राष्ट्रपति द्वारा (चयन समिति : प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, गृहमंत्री)



- **कार्यकाल** : 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (वर्ष 2019 में संशोधन के बाद)
- **वेतन भत्तों का निर्धारण** : केंद्र सरकार
- **पुनर्नियुक्ति**: पात्र
- **कार्यकाल समाप्त होने के बाद** : सरकार के साथ रोजगार निषिद्ध है।
- **शक्ति**: सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
- **सीमाएँ**:
  1. कथित उलंघन के 1 वर्ष बाद मामलों की जाँच नहीं कर सकता।
  2. सशस्त्र बलों पर सीमित अधिकार।
  3. सिफारिशें बाध्यकारी नहीं।
- **वर्तमान अध्यक्ष**: वी. रामसुब्रमण्यन

कार्य :

## Functions of the State Human Rights Commission



## संसदीय प्रश्न : न्यायपालिका सशक्तीकरण

### चर्चा में क्यों?

- निम्नलिखित जानकारी विधि एवं न्याय राज्यमंत्री और संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर के रूप में साझा की।

**Digital India** Power to Empower

**NIC** एन आई सी National Informatics Centre

### E-COURTS

Transforming Justice delivery by ICT enablement of Courts

**7 SIMPLE WAYS TO GET INFORMATION ON ANY COURT CASE ANYWHERE AND ANY TIME**

- 01 eCourts Services Mobile App
- 02 eCourts Website
- 03 SMS PULL
- 04 Information Kiosks
- 05 Email
- 06 Judicial Service Centres (JSCs)
- 07 SMS Push

**Unique Features**

- Free & Open Source software based project
- Single unified portal across the country (ecourts.gov.in)
- QR code to access case details

### मुख्य बिन्दु:

#### ई-कोर्ट्स मिशन प्रोजेक्ट :

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत, भारतीय न्यायपालिका के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास हेतु यह परियोजना वर्ष 2007 से कार्यान्वित की जा रही है।

#### 3 चरण:

- पहला चरण (वर्ष 2011 से 2015) : अदालतों का कम्प्यूटरीकरण व कनेक्टिविटी।
- दूसरा चरण (वर्ष 2015 से 2023) : न्यायिक सेवाओं हेतु ICT सुविधाएँ विकसित करना।

# Daily Current Affairs

Date : 13 March, 2026



- तीसरा चरण (वर्ष 2023 से 2027) : ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, वर्चुअल व हाइब्रिड सुनवाई, अभिलेखों का डिजिटलीकरण, सार्वजनिक पहुँच।
- राजस्थान में इस परियोजना के तहत 31 जनवरी, 2026 तक 1098 ई- कोर्ट्स संचालित है।
- इसके तहत वर्ष 2014 से वर्ष 2025 के मध्य देश के न्यायालयों द्वारा प्रतिवर्ष दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या में 169 की वृद्धि व निपटाए गए मामलों की संख्या में 207% की वृद्धि दर्ज की गई।

## न्यायिक अवसंरचना हेतु केंद्र प्रायोजित योजना:

- राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के संसाधनों को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार वर्ष 1993-94 से जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका हेतु बुनियादी ढाँचे से जुड़ी सुविधाओं के लिए कार्यान्वित कर रही है।
- इस योजना में 5 घटक शामिल हैं; न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों हेतु आवासीय इकाइयाँ, वकीलों के भवन, शौचालय परिसर और डिजिटल कम्प्यूटर कक्ष।
- वर्तमान में देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात लगभग 22 न्यायाधीश प्रति दस लाख जनसंख्या है।
- **डिजिटल कोर्ट व जस्टआईएस ऐप:** कागज रहित न्यायालय हेतु डिजिटल कोर्ट एक वेब आधारित पहल है जबकि जस्टआई ऐप लंबित मामलों की निगरानी व निपटान में सहायता करता है।

--:24:--

## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

### शैडो फ्लीट (Shadow Fleet)

#### चर्चा में क्यों?

- होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से अधिकतर वैध टैंकर का आवागमन बंद हो गया है, लेकिन वैश्विक शैडो फ्लीट के जहाज सामान्य नियमों के बाहर संचालित होते हुए तेल का परिवहन जारी रखे हुए हैं।



#### मुख्य बिन्दु:

#### शैडो फ्लीट: (डार्क फ्लीट)

- यह जहाजों के उस समूह को संदर्भित करता है जो अपने वास्तविक शुरुआत स्रोत, स्वामित्व आदि को छुपाते हैं तथा प्रतिबंधित या उच्च जोखिम वाली वस्तुओं का परिवहन करने के लिए भ्रामक शिपिंग गतिविधियों पर भरोसा करते हैं।

# Daily Current Affairs

Date : 13 March, 2026



- आधुनिक शैडो फ्लीट का विस्तार, 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद तेजी से हुआ, क्योंकि कई देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वैकल्पिक परिवहन तरीकों की आवश्यकता बढ़ गई।
- शैडो फ्लीट के जहाज आमतौर पर अपने रेडियो ट्रांसपोंडर (AIS) बंद कर देते हैं, जिससे जहाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती।
- समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जहाजों की प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए रेडियो ट्रांसपोंडर को चालू रखना अनिवार्य करता है।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

--:26:--

## खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)

### चर्चा में क्यों?

- भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की ओर से बहरीन द्वारा प्रस्तुत उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की गई है। इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में मतदान होना है।



### मुख्य बिन्दु:

#### खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)

- **मुख्यालय:** रियाद (सऊदी अरब)
- **स्थापना:** 25 मई, 1981
- **सदस्य (6):** संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत।
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों के बीच समन्वय, एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देकर अधिक क्षेत्रीय एकता सुनिश्चित करना।

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

### तेहरान में ब्लैक रेन

#### चर्चा में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तेल सुविधाओं पर हुए हमलों के बाद तेहरान में "काली बारिश" और जहरीले वायु प्रदूषण की चेतावनी दी है।

#### मुख्य बिन्दु:

##### ब्लैक रेन क्या है

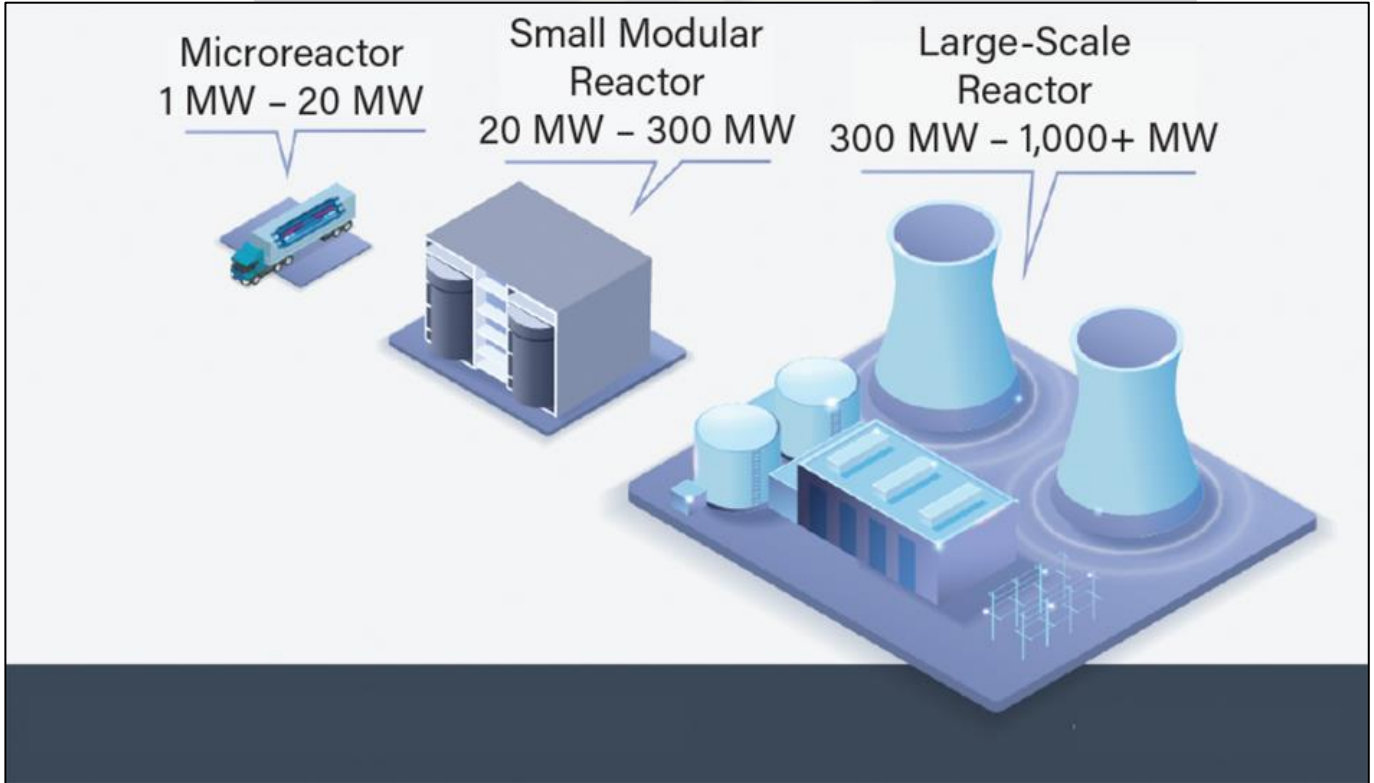
- "काली बारिश" से तात्पर्य उस वर्षा से है जो कालिख, राख, तेल के कणों और रासायनिक प्रदूषकों से दूषित होती है और जो बड़ी आग या विस्फोट के बाद वायुमंडल में छोड़ी जाती है।
- साफ पानी की बूंदों के बजाय, बारिश में गहरे, तैलीय कण होते हैं, जिससे यह काला या भूरा दिखाई देता है।
- इस तरह की बारिश आमतौर पर तब होती है जब बड़े पैमाने पर लगी आग से प्रदूषक हवा में फैल जाते हैं और बारिश इन कणों को जमीन तक पहुँचने से पहले ही सोख लेती है।
- ऐतिहासिक रूप से, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमलों के बाद भी इसी तरह की घटनाएँ देखी गई थीं, जब रेडियोधर्मी कालिख और मलबा बारिश के पानी में मिल गया था।

## ⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

### स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)

#### 📣 चर्चा में क्यों?

- भारत तीन विभिन्न प्रकार के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) विकसित कर रहा है।



#### 📌 मुख्य बिन्दु:

- IAEA के अनुसार SMRs बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लघुरूप हैं, जो प्रति मॉड्यूल 300 मेगावाट तक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स की क्षमता का लगभग एक-तिहाई है।

#### भारत के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)

- जहाँ SMRs पूरी तरह से एक नई अवधारणा हैं, वहीं भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs) भारत की मौजूदा प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित हैं।

# Daily Current Affairs

Date : 13 March, 2026



परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) द्वारा विकसित किए जा रहे 3 SMR मॉडल्स:

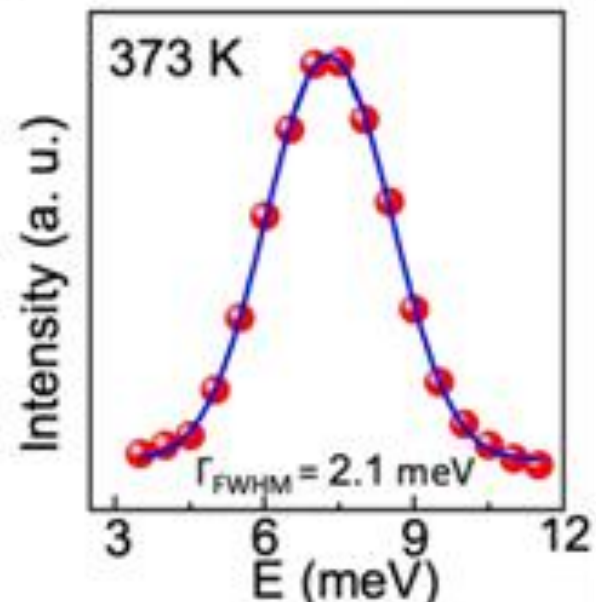
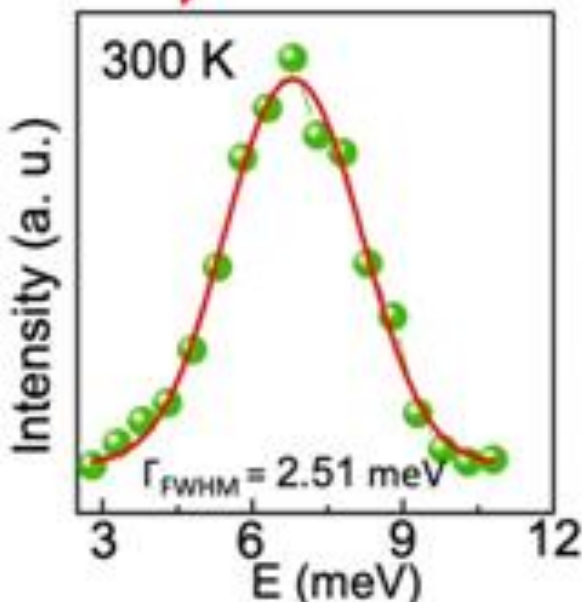
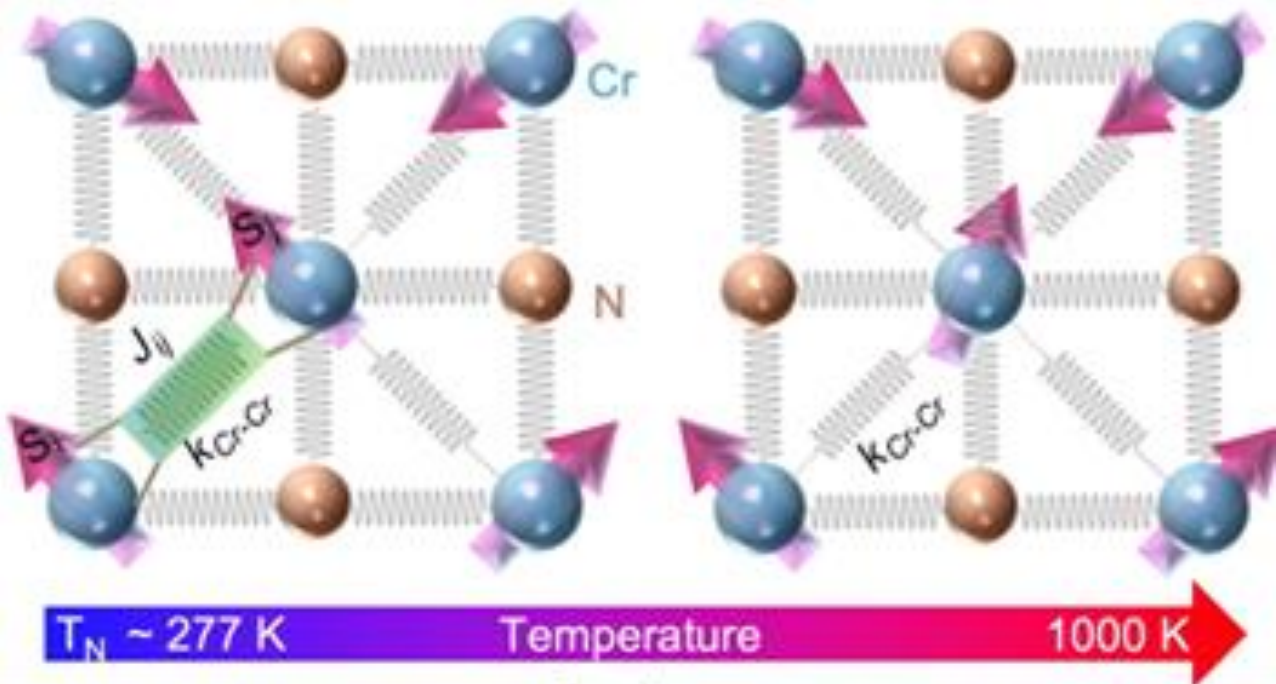
- **भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR) 200MWe:** इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- यह PWR (प्रेसराइज्ड वॉटर रिएक्टर) तकनीक पर आधारित है। इसमें ईंधन के रूप में अल्प संवर्धित यूरेनियम का उपयोग किया जाएगा। इसका निर्माण तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र में किया जाना प्रस्तावित है।
- **SMR-55MWe:** यह भी PWR तकनीक पर आधारित है और इसमें ब्लॉक-टाइप, अत्यधिक मॉड्यूलर डिजाइन की सुविधा है। इसका निर्माण भी तारापुर में होगा।
- **5 MW तक का हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर:** इसका उद्देश्य हाइड्रोजन उत्पादन है। इसे BARC विज्ञान, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा।

--:30:--

## मैग्नेटिक सेमीकंडक्टरों में हीट ट्रांसपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक सेमीकंडक्टरों में हीट ट्रांसपोर्ट को समझने में सफलता प्राप्त की है, जो स्पिनट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक मेमोरी और क्वांटम डिवाइसेज जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है।



--:31:--

## मुख्य बिन्दु:

- **प्रकाशन:** साइंस एडवांसेज पत्रिका।
- **शोधकर्ता:** बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) में प्रोफेसर बिवास साहा के नेतृत्व में।
- **सहयोग :** भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरूवनंतपुरम और लिंगोपींग विश्वविद्यालय, स्वीडन, एसपीआरिंग-8 (जापान), DESY (जर्मनी)।
- **परिचय:** परंपरागत सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ने पर ऊष्मीय चालकता घटती है, जिसका मुख्य कारण ऊष्मा संचारित करने वाले लेटिस वायब्रेशंस (जिन्हें फोनन कहा जाता है) की बढ़ी हुई स्केटरिंग है। हालांकि कई मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर इस नियम का उल्लंघन करते हैं और अपने मैग्नेटिक, ट्रांजिशन तापमान से ऊपर थर्मल चालकता में असामान्य वृद्धि प्रदर्शित करते हैं जैसे: क्रोमियम ऑक्साइड।
- **शोध:** बिवास साहा के नेतृत्व वाले दल ने इस घटना के लिए जिम्मेदार अंतर्निहित तंत्र की पहचान करने वाले प्रत्यक्ष प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं।
- अध्ययन से ज्ञात होता है कि मैग्नेटिक सेमीकंडक्टरों में हीट ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करने में फोनीन और मैग्नेटिक स्पिन उतार-चढ़ाव के मध्य मजबूत संयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- शोधकर्ताओं ने अत्याधुनिक तापमान निर्भर अप्रत्यास्थ एक्स-रे प्रकीर्णन तकनीक का उपयोग कर मैग्नेटिक फेज ट्रांजिशन के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली एपिटैक्सियल CRN थिन फिल्मों में फोनन लाइफटाइम को सीधे मापा।

# Daily Current Affairs

Date : 13 March, 2026



- **निष्कर्ष :** एकोस्टिक फोनोन, जो ऊष्मा के प्राथमिक वाहक है, मैग्नेटिक स्पिन उतार-चढ़ाव के साथ तीव्र अतः क्रियाओं के कारण नील टेम्प्रेचर के निकट तीव्र डम्पिंग अनुभव करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है लेग रेंज मैग्नेटिक क्रम कमजोर होता जाता है तथा फोनोन का जीवनकाल असामान्य रूप से बढ़ जाता है। जो पारंपरिक सिद्धांतों के विपरीत है।

- **महत्त्व:**

1. यह शोध मैग्नेटिक सेमीकंडक्टरों में बढ़ी हुई थर्मल चालकता के साथ स्पिन उतार-चढ़ाव को जोड़ने वाला पहला प्रत्यक्ष प्रयोगिक प्रमाण प्रदान करता है।
2. स्पिन - लैटिस अतः क्रियाओं द्वारा ऊष्मा प्रभाव को समझकर मैग्नेटिक, स्पिन्ट्रॉनिक और क्वांटम डिवाइसिज में तापीय प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ ज्ञात की जा सकती है, जहाँ ऊष्मा अपव्यय एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

--:33:--

## सी-डॉट और "फ्रॉडप्रो"



### चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) को स्वदेशी AI-आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान "फ्रॉडप्रो" के लिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, 2026 (MWC, 2026) में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है।



## मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 MOBILE WORLD CONGRESS 2026 THEME: "THE IQ ERA"

- Mobile World Congress 2026 स्पेन के बार्सिलोना शहर में 2 से 5 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और तकनीक उद्योग का सम्मेलन है।
- इस साल MWC 2026 की थीम "The IQ Era" रखी गई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी के मेल पर आधारित है।
- भारत के केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया।
- मंत्री जी ने "Breaking the Cost Barrier" विषय पर भाषण दिया और कहा कि सस्ती इंटरनेट सेवा हर नागरिक का अधिकार होनी चाहिए।
- सम्मेलन में भारत पवेलियन (Bharat Pavilion) का उद्घाटन किया गया, जिसमें 40 भारतीय कंपनियों ने अपनी तकनीक प्रदर्शित की।
- भारत पवेलियन में 5G नेटवर्क, सैटेलाइट संचार, AI, IoT और अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर जैसी तकनीकों को दिखाया गया।
- मंत्री जी ने India Mobile Congress (IMC) 2026 का ऐलान किया, जो 7 से 10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में होगा।
- Ericsson, Nokia, Meta, Qualcomm और Intel जैसी बड़ी वैश्विक कंपनियों से मुलाकात कर भारत के डिजिटल भविष्य पर चर्चा की गई।
- इस सम्मेलन में भारत ने यह संदेश दिया कि वह एक सुरक्षित, सस्ती और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल महाशक्ति बन रहा है।

# Daily Current Affairs

Date : 13 March, 2026



**मुख्य बिन्दु:**

**मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC), 2026:**

- **आयोजन :** मार्च, 2026 में बार्सिलोना (स्पेन)
- **वर्ष 2026 का विषय:** "The IQ Era"
- **आयोजक:** ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (GSMA)
- **विशेषता:** यह मोबाइल और प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है।  
**"फ्रॉडप्रो"**
- **परिचय:** यह एक उन्नत AI/ML संचालित धोखाधड़ी पहचान प्लेटफॉर्म है।
- **डिज़ाइन व विकास :** C-DOT (दूरसंचार विभाग)
- **उद्देश्य:** दूरसंचार प्रणालियों को पहचान आधारित धोखाधड़ी से सुरक्षित करना।
- **वैश्विक मान्यता:** MWC, 2026 के दौरान, इस समाधान ने सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्लोबल मोबाइल (ग्लोमो ) पुरस्कारों के शीर्ष फाइनलिस्टों में स्थान प्राप्त किया है।
- **तैनाती:** यह समाधान दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और संचार साथी पोर्टल के हिस्से के रूप में तैनात किया गया है।

--:35:--

## CE-20 क्रायोजेनिक इंजन

### चर्चा में क्यों?

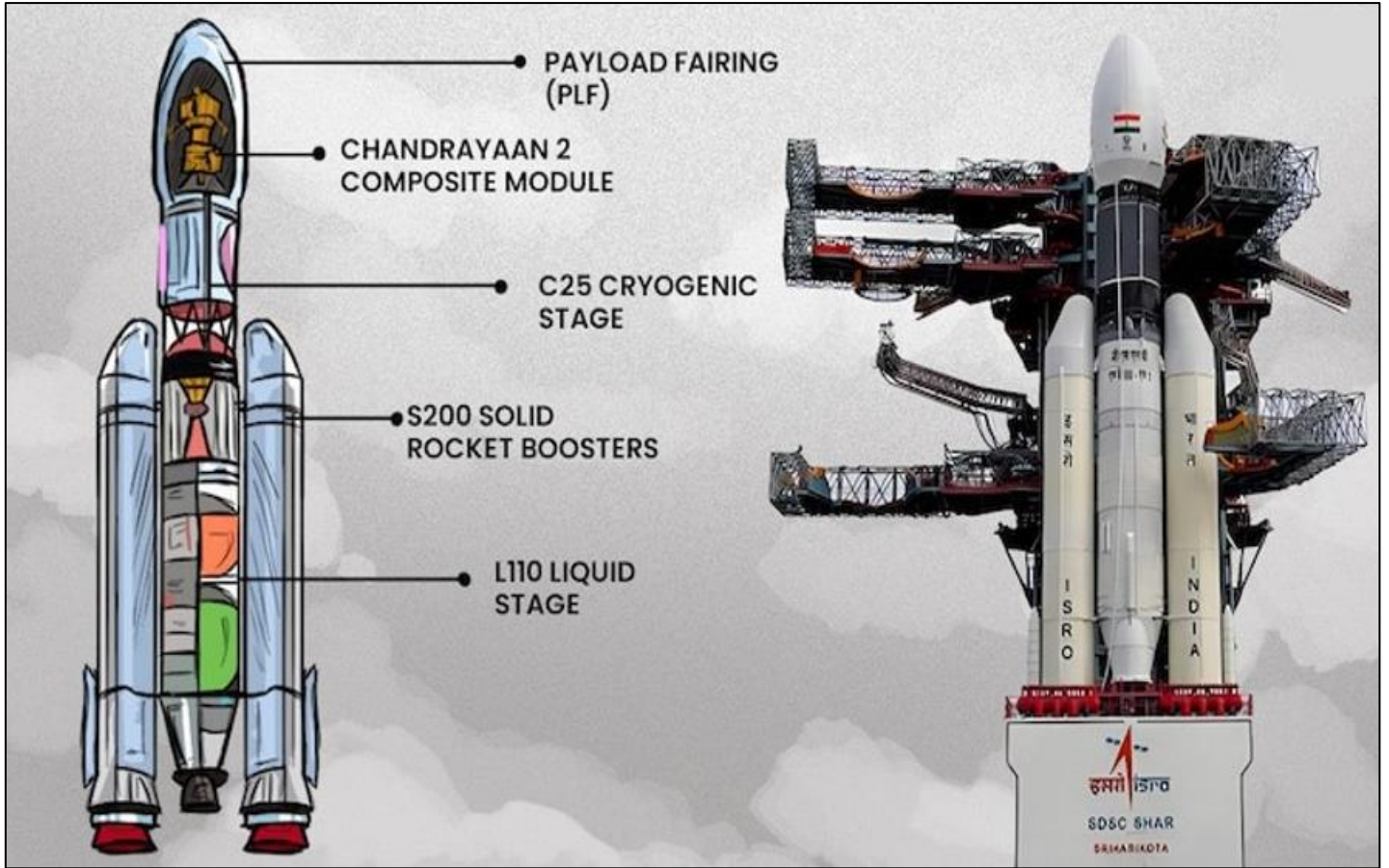
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया।



### मुख्य बिन्दु:

- **परीक्षण** : 12 मार्च, 2026 को महेद्रगिरि (तमिलनाडु) स्थित इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स से किया गया।
- **महत्त्व** : CE-20 क्रायोजेनिक इंजन "लॉन्च व्हीकल मार्क-3" (LVM-3) के ऊपरी क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान में सुधार होगा।

## CE-20 क्रायोजेनिक इंजन:



- **परिचय :** यह एक रॉकेट ईंजन है जो ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों के रूप में द्रवीकृत गैसों का उपयोग करता है।

### प्रयुक्त ईंधन व ऑक्सीकारक:

- **तरल ऑक्सीजन (Lox):** ऑक्सीकारक जो 183°C पर द्रवीकृत हो जाता है।
- **तरल हाइड्रोजन (LH<sub>2</sub>) :** ईंधन जो - 253°C पर द्रवीकृत हो जाता है।

### विशेषताएँ:

1. ईंजन को पुनः चालू करने की क्षमता रखता है।
2. नोजल सुरक्षा प्रणाली के कारण कम कंपन।
3. उच्च दक्षता।